पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.490

महिला थाना कांड सं.-72 वर्ष-2021, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर

==========

लक्ष्मण दास, पुत्र- स्व. बालेश्वर दास, निवासी- मोहल्ला- जे.पी. लेन, रोड नं-06, कान्हौली विष्णुदत्त, आर.के. आश्रम, थाना-बेला, जिला- मुजफ्फरपुर

.....अपीलार्थी/यों

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थी/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री प्रणव कुमार, अधिवक्ता
		श्री राजीव रंजन सं.-द्वितीय, अधिवक्ता
		सुश्री प्रियंका कुमारी, अधिवक्ता
		सुश्री अंजना गुप्ता, अधिवक्ता
		सुश्री कुमारी सीमा सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए	:	श्री बिपिन कुमार, अपर लोक अभियोजक
सूचना देने वाले के लिए	:	श्री सुरेंद्र किशोर ठाकुर, अधिवक्ता
		सुश्री वाई. माधवी, अधिवक्ता

==========

भारतीय दंड संहिता---धारा 376---पोक्सो अधिनियम, 2012---धारा 6, 42---दंड प्रक्रिया संहिता---धारा 164---उस निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील जिसके तहत अपीलकर्ता को अपनी बेटी (पीड़िता) के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया था---अपीलकर्ता की ओर से तर्क कि मामला दर्ज करने का एकमात्र उद्देश्य अपीलकर्ता

का किसी अन्य महिला से विवाह और अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार था---आगे तर्क यह कि शुरू में अपीलकर्ता के असंयमित तरीकों पर जांच डालने के गुप्त उद्देश्य से मामला दर्ज किया गया था, जिस आरोप से इनकार किया गया और फिर चूंकि अपीलकर्ता पूरी संपत्ति पीड़िता, उसके भाई और उसकी मां को देने के लिए सहमत नहीं था, इसलिए आरोपों को फिर से ट्रायल कोर्ट के समक्ष दोहराया गया।

निष्कर्ष:- पीड़िता और अन्य दो गवाहों ने 164 सीआरपीसी में मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान जो इस बात का उचित विचार देता है कि मामला शुरू में क्यों दर्ज किया गया था --- उन्हें किसी भी डर से घबराने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि अपीलकर्ता पहले से ही जेल में बंद था और किसी भी गवाह ने किसी व्यक्ति द्वारा पीड़िता या अन्य परिवार के सदस्यों को मामले को जारी रखने के लिए धमकी देने की कोई शिकायत नहीं की थी --- कि पीड़िता और उसकी मां ने मामला दर्ज करने के लिए एक विशेष समय चुना, इस मामले को पूरी तरह से भरोसे के लायक नहीं बनाता है --- अगर यह सच होता कि पीड़िता के साथ उसके पिता ने यौन उत्पीड़न किया था, तो किसी भी तरह की धमकी उन्हें हर मंच के सामने आरोप को दोहराने के अलावा कुछ और कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी -- यौन उत्पीड़न के मामलों में, एकमात्र गवाही पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन केवल तभी जब ऐसे गवाह का बयान सत्यता की कसौटी पर खरा उतरे और अन्यथा नहीं --- यौन अपराध की पीड़िता को कभी भी साथी अपराधी के बराबर नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि वह अपराध की पीड़िता है, और किसी और पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन केवल तभी जब उसका साक्ष्य पूरी तरह से सच प्रतीत होता है विश्वसनीय---पीड़िता और अन्य 2 गवाहों ने खुद को उत्कृष्ट गवाह साबित नहीं किया है---आलोचना किया गया निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश रद्द किया गया--- अपील स्वीकार की गई। ***(पैरा 23, 34, 35, 41-44)***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री नानी टैगिया

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तारीखः 12-12-2023

हमने अपीलार्थी और पीड़िता की ओर से क्रमशः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रणव कुमार और सुश्री वाई. माधवी को सुना है। विद्वान एपीपी श्री बिपिन कुमार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2. अपीलकर्ता, जो पीड़िता का पिता है, को महिला थाना कांड संख्या 72/2021 के संबंध में विद्वान 7वें अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, पोक्सो (डब्ल्यू), मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 23.02.2023 को पारित निर्णय के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया है। दिनांक 28.02.2023 के आदेश के तहत उसे शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है, तथा 1,00,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है, जिसे अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस प्रकार अदा किया गया जुर्माना पीड़िता को दिए जाने का निर्देश दिया गया है, जो अपीलकर्ता की पुत्री है।

3. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुज़फ़्फ़रपुर से भी पीड़िता को 5,00,000 रुपये की मुआवजा राशि देने का अनुरोध किया गया है।

4. अधिनियम की धारा 42 को देखते हुए पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत कोई अलग सजा नहीं दी गई है।

5. एक चौदह वर्षीय लड़की की दर्दनाक कहानी ने दुनिया के सबसे घृणित अपराधों में से एक हो सकती थी, लेकिन यह आरोप पूरी तरह से निराधार पाया गया।

6. दिनांक 12.09.2021 को पीड़िता (अ.सा.1) ने महिला पुलिस थाना, मुज़फ़्फ़रपुर के प्रभारी अधिकारी के सामने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सितंबर, 2018 के महीने में, अपीलार्थी ने उसके साथ इलाज करने के बहाने उसके साथ यौन संबंध बनाए और उसे घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी। हालाँकि, उसने इस तथ्य को अपनी माँ (अ.सा.3) को बताया, जिन्होंने बदले में, पीड़िता के भाई को सूचित किया, जो मुंबई में रहने वाला एक 24 वर्षीय व्यक्ति था, जिसके बाद लिखित रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

7. पीड़िता के अनुसार, अपीलकर्ता ने उसकी मां के साथ अपनी शादी के दौरान अप्रैल, 2021 में दोबारा शादी कर ली थी।

8. उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर, अपीलार्थी के खिलाफ जांच के लिए भा.दं.सं. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत 2021 का महिला थाना मामला संख्या 72 दिनांक 12.09.202 दर्ज किया गया था।

9. अपीलार्थी के बारे में कहा जाता है कि वह मोतिहारी में तैनात उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का कर्मचारी है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट दर्ज होने के एक दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

10. पीड़िता ने 14 सितंबर, 2021 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उसने अपने पिता द्वारा किसी भी यौन कृत्य

के अधीन होने से इनकार किया था। वास्तव में, उसने मजिस्ट्रेट के सामने बताया कि उसके पिता के अपमानजनक व्यवहार के कारण मामला दर्ज किया गया था ताकि उसे दूर रखा जा सके।

11. इसी तरह के बयान पीड़िता के भाई और मां ने उसी दिन मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत दिए थे। वास्तव में, पीड़िता के भाई ने कहा था कि उसकी मां गुस्सैल स्वभाव है और उनके बीच कुछ वैवाहिक विवाद के कारण, विषय की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

12. पीड़िता की माँ अपीलार्थी से व्यथित थी क्योंकि अपीलार्थी ने एक अन्य महिला से शादी की थी जिसके साथ वह मोतिहारी में रह रहा था।

13. हालाँकि, मुकदमे में, पीड़िता ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है। उसने अपीलार्थी पर कई बार बलात्कार करने का आरोप दोहराया है। उसने विचारण न्यायालय के समक्ष यह भी कहा है कि अपीलार्थी ने कभी भी उसके भाई को घर नहीं आने दिया। जब भाई मुंबई से घर आया तो उसे घटना के बारे में बताया गया और उसके बाद उसके कहने पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

14. धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत अपने बयान के संबंध में, उसने विचारण न्यायालय के समक्ष खुलासा किया कि ऐसा बयान उसने, उसकी माँ और भाई ने अपीलार्थी द्वारा दबाव और धमकी के तहत दिया गया था।

15. मुकदमे में पीड़िता के भाई और माँ द्वारा भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं, जिनसे क्रमशः अ.सा. 2 और 3 के रूप में पूछताछ की गई है। हालाँकि, पीड़िता के भाई ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी जिरह में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने केवल मौखिक रूप से पुलिस को सूचित किया था कि उन्होंने अपनी माँ से

पूछताछ की थी, जिन्होंने घटना के बारे में बताया था। उन्होंने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत कोई आरोप नहीं लगाने का कारण अपने पिता द्वारा दी गई धमकियों को भी बताया है, जो उस समय जेल में बंद थे।

16. दो अज्ञात व्यक्तियों ने पीड़िता और उसे आरोप का समर्थन नहीं करने के लिए धमकी दी थी। पीड़िता की माँ (अपीलकर्ता की पत्नी) ने स्वीकार किया कि उसकी शादी एक कठिन दौर से गुजर रही थी और इसलिए उसने मामला दर्ज कराया था। हालाँकि, मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा बयान अपीलार्थी द्वारा धमकी के तहत दिया गया था। यह सुझाव कि आरोप इसलिए लगाया गया है क्योंकि अपीलकर्ता ने दूसरी महिला से शादी कर ली है, को खारिज कर दिया गया।

17. यह हमें उस पुलिस अधिकारी के बयान की ओर ले जाता है, जिसने प्राथमिकी दर्ज की थी और पीड़िता तथा अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए थे। उसने इस बात से पूरी तरह इनकार किया है कि पीड़िता ने कभी उसे यह नहीं बताया था कि अपीलकर्ता ने उसे पेट दर्द के इलाज के बहाने निर्वस्त्र किया था और वह अपने यौन कृत्य को उस कृत्य से जोड़ रहा था जिसे पीड़िता को शादी के बाद भुगतना पड़ता। अधिकारी ने इस बात से भी इनकार किया है कि पीड़िता के भाई ने उसे मौखिक रूप से बताया था कि उसकी माँ ने उसे इस घटना के बारे में बताया था जब वह मुंबई से वापस आया था।

18. पीड़िता ने जब अपना बयान दर्ज कराया था, तब उसे बार-बार बलात्कार की बात भी नहीं बताई गई थी।

19. पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई।

20. मेडिकल रिपोर्ट में हालांकि दर्ज किया गया है कि हाइमेन फट गया था, लेकिन जांच करने वाले डॉक्टर द्वारा किसी भी चोट का पता नहीं लगाया जा सका। परीक्षण में डॉक्टर की अ.सा. 5 के रूप में जाँच की गई है।

21. इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मामला दायर करने का एकमात्र उद्देश्य अपीलार्थी का किसी अन्य महिला के साथ विवाह और अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसका दुर्व्यवहार था।मामला दर्ज करने का उद्देश्य अपीलार्थी को घर पर दुर्व्यवहार करने से रोकना था।

22. यह भी तर्क दिया गया है कि गवाहों का यह बयान कि उन्होंने धमकियों के कारण मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले का समर्थन नहीं किया था, स्वीकार्य नहीं है। मजिस्ट्रेट के सामने गवाह किसी डर में नहीं थे। वास्तव में, अपीलार्थी लंबे समय से जेल में बंद था। पीड़िता के भाई या माँ या खुद पीड़िता द्वारा दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने एक अलग बयान देने की धमकी देने के बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

23. उस मामले में, यह तर्क दिया गया है कि यह काफी तार्किक प्रतीत होता है कि शुरू में अपीलकर्ता के असंयमित तरीकों पर रोक लगाने के गुप्त उद्देश्य से मामला दर्ज किया गया था, जिस आरोप को खारिज कर दिया गया था और फिर चूंकि अपीलकर्ता पूरी संपत्ति पीड़िता, उसके भाई और उसकी मां को देने के लिए सहमत नहीं था, इसलिए आरोपों को फिर से विचारण न्यायालय के समक्ष दोहराया गया।

24. इस मामले के जांच अधिकारी का बयान, जिसमें उन्होंने गवाहों द्वारा पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किए जाने तथा उसके साथ इस तरह के दुराचार किए जाने की बात से पूरी तरह इनकार किया है, इस आरोप को बहुत ही संदिग्ध बनाता है।

25. अपीलकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि वह बिना किसी गलती के मामले दर्ज होने के अगले दिन से हिरासत में है। भा.दं.सं. की धारा 313 के तहत उसका बयान भी उसके झूठे आरोप का कारण बताता है। किसी न किसी कारण से उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया था, लेकिन यह उसकी पत्नी (अ.सा. 3) की जानकारी में था, जिसने उसकी दूसरी शादी के बारे में कोई आपत्ति नहीं जताई थी। हालांकि यह जीवित पति या पत्नी की सहमति नहीं हो सकती है, लेकिन यह तर्क दिया गया है कि यह अपीलकर्ता के पूरे परिवार के उनके खिलाफ जाने का कारण बताता है। इस बात की संभावना हो सकती है कि गवाह अपीलकर्ता के खिलाफ गवाही दें कि वह अपनी संपत्ति को उस तरह से साझा करने के लिए सहमत नहीं था, जिस तरह से वे चाहते थे।

26. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को शेष जीवन के लिए सजा सुनाने में गलती की है, जो सजा केवल उच्च न्यायालयों द्वारा ही लगाई जा सकती है ***[भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन एवं अन्य 2016 (7) एससीसी 1 देखें]।***

27. मुखबिर की विद्वान अधिवक्ता सुश्री वाई. माधवी ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सही विश्लेषण किया है क्योंकि पीड़िता, उसके भाई और मां की विश्वसनीयता और भरोसेमंदता पर संदेह करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। लिखित रिपोर्ट के देरी से दर्ज होने को अच्छी तरह से समझाया गया है।

28. उसने प्रस्तुत किया है कि पीड़िता और उसकी माँ या उसके भाई के लिए अपीलार्थी के कृत्य के खिलाफ खुलकर सामने आना सामाजिक रूप से बहुत मुश्किल होता, क्योंकि इससे केवल उनका सामाजिक बहिष्कार होता।

29. पीड़िता के रिश्तेदारों द्वारा यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि से जुड़े मामलों के संबंध में कानून अब तक अच्छी तरह से सुलझा लिए गए हैं। अभियोक्ता के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर ही दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है।

30. सुश्री माधवी का तर्क है कि मुकदमे में न केवल पीड़िता बल्कि उसकी माँ और भाई ने भी आरोप का समर्थन किया है। वर्ष 2018 में अपीलार्थी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को लागू नहीं करने के लिए अच्छे कारण दिए गए हैं और निचली अदालत ने पीड़िता सहित तीनों गवाहों द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य की उत्कृष्ट गुणवत्ता को देखने के बाद इसे स्वीकार कर लिया है।

31. इस मामले में, यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को शेष जीवन के लिए सजा देना कानून के दायरे में नहीं आता है, लेकिन जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि का सवाल है, अदालत में पीड़िता के साक्ष्य के आधार पर इसमें कोई गलती नहीं की जा सकती है।

32. राज्य के विद्वान वकील द्वारा भी इसी प्रकार के तर्क प्रस्तुत किये गये।

33. पूरे मामले की विस्तार से जांच करने के बाद, हमने पाया है कि घटना के तीन साल बाद पीड़िता द्वारा मामला दर्ज कराने का कोई कारण था।

34. अपीलकर्ता की दूसरी शादी अप्रैल, 2021 के महीने में हुई थी। उसके पांच महीने बाद मामला दर्ज किया गया। पीड़िता के अनुसार, मुजफ्फरपुर में उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया। हालांकि, जिरह के दौरान उसने कहा है कि उसे मोतिहारी में अपनी सौतेली मां के साथ रहने का भी मौका मिला था। उसने सौतेली मां के बारे में कोई शिकायत नहीं की, जिसके कारण अपीलकर्ता ने पीड़िता को संपत्ति का कोई हिस्सा

नहीं दिया। प्राथमिकी में बताए गए कृत्य का विवरण हालांकि विचारण न्यायालय के समक्ष दोहराया गया था, लेकिन मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के समक्ष नहीं बताया गया।

35 पीड़िता या उसकी माँ और भाई को इस कारण से उचित नहीं ठहराया जाता है कि पीड़िता ने पुलिस स्टेशन आने और मामले के बारे में रिपोर्ट करने में अपने डर को दूर कर लिया था। पीड़िता सहित उन सभी ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने 164 दं.प्र.सं. बयान में मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया, यह इस बात का एक उचित विचार देता है कि मामला शुरू में क्यों दर्ज किया गया था। सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि जब वे मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने-अपने बयान दे रहे थे, तो उन्हें कोई डर नहीं था।

36. अपीलार्थी के पहले ही जेल में बंद होने के कारण उनके लिए किसी भी तरह के डर से परेशान होने का कोई अवसर नहीं होता।

37. हमें किसी भी गवाह की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है कि किसी व्यक्ति ने पीड़िता या परिवार के अन्य सदस्यों को मामला जारी रखने के लिए धमकी दी है।इसलिए गवाहों का आरोप बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं लगता है।

38. मामला दर्ज करने का समय भी महत्वपूर्ण है।

39. वर्ष 2018 में पहली बार पीड़िता को इस तरह की पीड़ा का सामना करना पड़ा था।इसके बाद कई साल बीत चुके थे। अपीलार्थी मोतिहारी में रह रहा था, क्योंकि वह मोतिहारी में स्थित बैंक की एक शाखा में तैनात था। पीड़िता अपनी मां के साथ मुजफ्फरपुर में रहती थी। पीड़िता का भाई मुंबई में अपनी पढ़ाई कर रहा था। इस

पृष्ठभूमि में, परिवार के किसी सदस्य द्वारा किए गए अपराध के संबंध में खुले तौर पर सामने नहीं आने वाले परिवारों के रूढ़िवादी प्रकार को स्वीकार करना मुश्किल होगा।

40. कानूनी और नैतिक रूप से यह बात सत्य है कि यौन अपराध के पीड़िता को सह-अपराधी नहीं माना जाना चाहिए, साथ ही यह भी सत्य है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराने में परिवार के सदस्यों की अनिच्छा की रूढ़िवादिता को त्याग दिया जाना चाहिए।

41. अपीलकर्ता हमेशा पीड़िता और उसकी माँ के साथ नहीं रहता था। पीड़िता और उसकी माँ के पास अपने भाई की सहायता से कानून की प्रक्रिया का सहारा लेने के कई अवसर थे, ताकि वे खुद को आगे के हमले से बचा सकें और साथ ही दोषियों को सजा दिला सकें। पीड़िता और उसकी माँ ने मामला दर्ज करने के लिए एक खास समय चुना, जिससे मामला पूरी तरह से भरोसे के लायक नहीं रह जाता। अगर यह सच होता कि पीड़िता के साथ उसके पिता ने यौन उत्पीड़न किया था, तो कोई भी धमकी उन्हें हर मंच पर आरोप दोहराने के अलावा कुछ और कहने पर मजबूर नहीं करती।

42. कोई इस बात पर सहमत हो सकता है कि मजिस्ट्रेट के सामने वे किसी खतरे में थे, लेकिन पुलिस अधिकारी के सामने भी, जहां पीड़िता अपनी मां के साथ गई थी, कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया था।न तो पीड़िता और न ही उसकी माँ को किसी पुलिस अधिकारी के सामने कोई धमकी दी गई थी।ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय बेटी द्वारा अपने पिता के खिलाफ लगाए गए आरोप से प्रभावित हुई थी, जिसका समर्थन उसके भाई और मां दोनों ने किया था।

43. हम पीड़िता, उसकी मां और भाई द्वारा लगाए गए आरोप को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। इस कारण से कि उन्होंने खुद को उत्कृष्ट गवाह साबित नहीं किया है।

44. इस बात का कोई खंडन नहीं है कि यौन हमले के मामलों में, एकमात्र गवाही पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब इस तरह के गवाह का संस्करण सच्चाई की परीक्षा के योग्य हो और अन्यथा नहीं।

45. सुश्री माधवी द्वारा संदर्भित सभी मामलों में *अर्थात* ***फूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 1520/2021; गणेशन बनाम राज्य, (2020) 10 एससीसी 573; संतोष प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (2020) 3 एससीसी 443; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मंगा सिंह, (2019) 16 एससीसी 759 और राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) बनाम पंकज चौधरी, (2019) 11 एससीसी 575,*** अभियोजन पक्ष के बयान तर्कसंगतता और सत्यता की कसौटी पर खरे उतरे।

46. वर्तमान परिस्थितियों में, साक्ष्य आरोप के सही होने के बारे में विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि यौन अपराध को कभी भी एक साथी के बराबर नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि वह अपराध की शिकार है, और आगे किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन केवल तभी जब उसका सबूत पूरी तरह से विश्वसनीय प्रतीत होता है।

47. हमने अपने आदेश पर गवाहों के बयान की अत्यंत संवेदनशीलता के साथ जांच की है, गवाहों के बयान में मामूली विसंगतियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, केवल इस कारण से कि यदि आरोप सही होते, तो पीड़िता या उसकी माँ के लिए वास्तव में आगे आना मुश्किल होता।

48. हालाँकि, पृष्ठभूमि के तथ्य हमें आश्वस्त नहीं करते हैं कि गवाह सही बयान दे रहे थे।

49. हमने व्यापक संभावनाओं के साथ मामले के रिकॉर्ड देखे हैं लेकिन आरोप में सच्चाई नहीं पा सके हैं।

50. अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

51. उपर्युक्त कारणों से, हम अपीलार्थी के निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को निरस्त कर देते हैं और उसे उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर देते हैं।

52. यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित या हिरासत में नहीं है तो उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

53. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और रिकॉर्ड के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजी जाए।

54. इस मामले के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

55. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा कर दिया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(नानी तागिया, न्यायमूर्ति)

कृष्ण/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।